Title: Need to enquire the matter of debt of crores of rupees arrears pending with M/s S.R. Steel company.

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने जो सवाल उठा रहा हूं, वह इस देश के गरीब किसान, मजदूर, जो भूखे-नंगे हैं, उनसे संबंधित है। आज सरकार और सरकार के मंत्रियों की जो चापलूसी करे और उनकी मेहरबानी हो जाए, तो कोई मेहनत नहीं, कोई परिश्रम नहीं और कोई धन लगाने की जरूरत नहीं है, वह खरबपति बन सकता है। यह इससे सिद्ध हो रहा है, एस.आर. कम्पनी जिसपर वित्तीय संस्थाओं का दस हजार करोड़ रुपए का कर्जा है, उसने ब्याज तो दूर मूलधन भी नहीं दिया है, उस के विरूध्द सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।

एस.आर. स्टील कम्पनी पर वित्तीय संस्थाओं का २००६ करोड़ रुपया का कर्ज ३० सितम्बर तक है। अभी तक न ब्याज दिया और न ही मूलधन दिया। अब सरकार ४५५ करोड़ रुपए और दे रही है, जब कि ३२५ करोड़ रुपया केवल ब्याज का है। कम्पनी के मालिक शशि रूईया और रवि रूईया, ये अप्रवासी भारतीय बन गए हैं, इनकी व्यक्तिगत गारंटी पर इन्हें कर्ज दिया जा रहा है। जब वे अप्रवासी भारतीय बन गए हैं तो उनकी व्यक्तिगत गारंटी का कोई मूल्य नहीं है । सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो इन्हें कर्ज दे रही है। हमारे जो गरीब या मध्यम वर्ग के उद्योग हैं उनको कोई मदद नहीं की जा रही है, गरीब किसानों के लिए दूसरा कानून है और एस.आर. कम्पनी के लिए दूसरा कानून है। अगर रूग्ण इकाइयां उन्हें दे दी जाएं तो हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन केवल एस.आर. कम्पनी को मदद दी जा रही है, जब कि उन्होंने न पिछला मूलधन दिया है, न ब्याज दिया है और न ही किश्त दी है। हम चाहते हैं कि सरकार और वित्त मंत्री जी सदन को स्पष्ट करें और बताएं कि जो हमारे करोड़ों गरीब हैं उनके पेट पर लात मार कर इस प्रकार का जो कार्य कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। अगर यह प्रवृत्ति बन गई कि देश के अंदर सरकारी पैसे, वित्तीय संस्थाओं के पैसे को लेकर खरबपति बनेंगे और सरकार उन्हें और कर्जा देगी गरीब किसान तहसील में ३०० रुपए पर बंद किया जाता है और एस आर कम्पनी १०,००० करोड़ रुपए की कर्जदार हैं, सरकार इस पर कार्यवाही करने की बजाए ४५५ करोड़ रुपए और दे रही है। इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या मजबूरी है?

... (व्यवधान)
महोदय, यह गंभीर मामला है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, अन्य लोगों ने भी नोटिस दिए हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : हमारी मांग है कि वित्त मंत्री जी बयान दें और सदन में स्पष्ट करें, क्योंकि गरीब की गाढ़ी कमाई पर लात मार कर पूरी लूट का मौका दिया जा रहा है। अगर इस तरह की प्रवृत्ति देश में बनी तो इस देश का गरीब बर्बाद होगा और सरकारी पैसे से ही कुछ मुट्ठीभर लोग खरबपति बनेंगे। इसलिए हम वित्त मंत्री जी और सदन से कहेंगे कि ऐसे सवालों पर मौन नहीं रहना चाहिए। यहां कई नेता बैठे हैं, हम चाहते हैं कि हम जो बोले हैं उस पर आप अपनी राय जाहिर करें और इसका विरोध करें।

हम चाहते हैं कि सरकार सदन में स्पष्ट करें कि उसके सामने कौन सी मजबूरी है, उन्हें कौन मजबूर कर रहा है? उस कम्पनी पर इतनी मेहरबानी क्यों है? १०,००० करोड़ रुपए की जो कर्जदार है, उसे कर्जा चुकाने के लिए सरकार और कर्ज दे रही है। हमारा यह कहना है कि सरकार सदन में स्पष्ट करे और अगर नहीं करेगी तो जो कुछ मोहन गुरुस्वामी जी कहा था, वह सच साबित हो रहा है। इसलिए इस पर सदन को मौन नहीं रहना चाहिए, चाहे सत्तापक्ष के माननीय सदस्य हो या विपक्ष के हों, क्योंकि यह देश के गरीबों की गाढ़ी कमाई के खून पसीने का पैसा है और इससे कुछ लोगों को खरबपति बनाया जा रहा है, जिनकी गारंटी का कोई मतलब नहीं है, उनकी गारंटी पर दिया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि वित्त मंत्री जी या संसदीय कार्य मंत्री जी सदन को स्थिति से अवगत करायें।

SHRI UTTAMRAO DHIKALE : Sir, I want to raise an important issue about my constituency. (Interruptions).

MR. SPEAKER: Please take your seat.

... (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN : Sir, I have given a notice at 8.30 a.m. (Interruptions).

MR. SPEAKER: Shri Ramesh Chennithala.

... (Interruptions)

SHRI UTTAMRAO DHIKALE : Sir, I also gave a notice around nine o'clock to raise an urgent matter...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seat. What is this? I am calling all the names. Please try to understand.

... (Interruptions)

SHRI UTTAMRAO DHIKALE : Sir, I gave the notice around nine o'clock. I want to raise an urgent matter concerning my constituency...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seat. This is too much. It is the discretion of the Chair to call the names. <